भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3310
दिनांक 20 मार्च, 2025

वैश्विक ऊर्जा भागीदारी

3310. श्री मनीष जायसवाल:
श्री बिभु प्रसाद तराई:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैश्विक ऊर्जा भागीदारी भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और संक्रमण लक्ष्यों के साथ किस प्रकार अनुरूप है;
(ख) भारत के वैश्विक ऊर्जा सहयोग में नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन की क्या भूमिका है;
(ग) भारत हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधनों और कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों में विदेशी निवेश को किस प्रकार आकर्षित करने की योजना बना रहा है; और
(घ) क्या ऊर्जा दक्षता और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अनुसंधान और विकास के संबंध में वैश्विक ऊर्जा फर्मों के साथ कोई सहयोगात्मक प्रयास किए जा रहे हैं और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए), अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए), संपन्नता के लिए भारत-प्रशांत आर्थिक ढाँचा (आईपीईएफ), जी20 के स्वच्छ ऊर्जा मिनिस्टीरियल, स्वच्छ कुकिंग मिनिस्टीरियल, ऊर्जा परिवर्तन कार्य-समूह, क्वाड के तहत ऊर्जा मंत्रियों की वार्ता, वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलन की आवाज और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) जैसे वैश्विक ऊर्जा संबंधी साझेदारी में भारत का नेतृत्व और भागीदारी के चलते भारत को ऊर्जा सुरक्षा, पहुँच और स्थिरता के सम्बन्ध में अपने विचार रखने और परिणामों/विचार-विमर्श को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है।

ऐसी वैश्विक ऊर्जा साझेदारियों में भारत की सुदृढ़ वकालत सर्वोत्तम परंपराओं को साझा करने, लचीली मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी विकास को आगे बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लिए कम लागत के वित्तपोषण की खोज के लिए अवसर प्रदान करती है।

सरकार ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र को स्वचालित मार्ग के अधीन 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए खोल दिया है, जो पूर्व-अनुमोदन आवश्यकताओं को समाप्त करता है। वर्ष 2070 तक निवल शून्य का समर्थन करने के निमित्त सरकार उन्नत जैव ईंधन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना, विशेष रूप से गैर-खाद्य बायोमास का उपयोग करने और कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) अवसंरचना में तेजी लाने का भी समर्थन कर रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्न के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देने के लिए, तेल कम्पनियाँ हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग सहित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला के विकास पर सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। इन पहलों से साझेदारी और विदेशी निवेशों के लिए अवसर खुल गए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उपक्रमों ने इलेक्ट्रिक वाहनों में एलिमिनियम-एयर बैटरी का समेकन, सीओ2 को अल्कोहल में इलेक्ट्रो-बायोकैटेलिटिक रूपांतरण के लिए प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट को अंतिम रूप देना, डीकार्बोनाइजेशन और लो- कार्बन अवसर, सतत विकास के लिए संयुक्त विशेषज्ञता का लाभ उठाना, स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकियाँ, प्रक्रिया स्वचालन, विक्रेता भुगतान प्रणाली को सुव्यवस्थित करना, तरंग ऊर्जा, अपतटीय अन्वेषण, उत्सर्जन निगरानी और ऊर्जा दक्षता समाधान आदि जैसे अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर वैश्विक ऊर्जा कम्पनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा सके।

****